

संस्करण : लखनऊ

वर्ष : 11

अंक : 145

पृष्ठ : 6

मूल्य : 1.00

लखनऊ-**बुधवार,24 सितम्बर 2025** लखनऊ, प्रयागराज ,ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 दीपोत्सव: दीवाली पर रोशन होगी अयोध्या,देव दीपावली**4** अमेरिकी आत्मघाती वीजा बंदिशें, भारत के नये अवसर**5** ईंडी के सामने तलब हुईं ह्यांग्दी बात फेम एक्ट्रेस

26 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे पैसे ट्रांसफर

75 लाख महिलाओं को मिलेगी महिला रोजगार योजना की पहली किस्त



पटना (एजेंसी)। 26 सितंबर 2025 का दिन बिहार की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से ऑनलाइ 2 रहकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त 10-10

हजार रु की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। बता दें कि 77,500 करोड़ यह राशि केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई

शुरूआत है। सिलाई-बुनाई, खेती या पशुपालन जैसे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह पहल बिहार की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदलने वाली साबित हो सकती है। योजना का मकसद: आत्मनिर्भर और सशक्त महिला महिला रोजगार

योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वे अपने परिवार और समाज में भी सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकेंगी। खास बात यह है कि रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं को उनके व्यवसाय की प्रगति के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह कदम महिलाओं को लंबे समय तक मजबूत आर्थिक आधार देने में सहायक साबित होगा। कौन और कैसे ले सकता है योजना का लाभ महिला रोजगार योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं, जो बिहार की स्थायी निवासी हैं। इसमें राज्य की ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकाश की महिलाएं शामिल हैं। योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए महिलाओं का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है। हालांकि, जिन

महिलाएं अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए भी यह अवसर खुला है। उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह की सदस्यता लेनी होगी। सदस्य बनने की प्रक्रिया सरल रखी गई है—इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा और आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सीधे अपने ग्राम संगठन या जीविका समूह के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। वहां समूह की प्रतिनिधि उन्हें फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने में सहायण करेगी। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मंजूरी, इन छह प्रस्तावों पर लगाई धामी सरकार ने मुहर



देहरादून, (एजेंसी)। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। तीसरा 1872 इंडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ राज्य सरकार देगी। रक्षपुर में बन रहे हैं पीएम आवास के भवन। चौथा दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। एएससीआईटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण करता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा।

पुनर्गठन मंजूर। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। तीसरा 1872 इंडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ राज्य सरकार देगी। रक्षपुर में बन रहे हैं पीएम आवास के भवन। चौथा दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। एएससीआईटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण करता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा।

मणिपुर में सेना-असम राइफलस का बड़ा ऑपरेशन, 9 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी हथियार बरामद

मणिपुर (एजेंसी)। स्पीयर कोर के नेतृत्व में भारतीय सेना और असम राइफलस ने 15 से 21 सितंबर, 2025 तक मणिपुर में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। मणिपुर पुलिस के साथ इन समन्वित प्रयासों ने तेंगनापाल, थौबल, इंफाल पूर्व, तामेंगलोंग, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और चंदेल सहित कई जिलों को निशाना बनाया। एकस पर साझा की गई एक पोस्ट में, भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने कहा कि इन अभियानों के दौरान नौ सक्रिय कैडर पकड़े गए। सुरक्षा बलों ने 36 हथियार, नशीले पदार्थ और अन्य युद्ध-संबंधी सामान बरामद किए। अभियान पहाड़ी और घाटी जिलों में चलाए गए, जो सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। ये संयुक्त अभियान मणिपुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं। इससे पहले, विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, असम राइफलस ने 18 सितंबर को चंपई जिले के सैखुम्फई के घने जंगलों में एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया था।

दिल्ली में कुटू का आटा खाने से करीब 200 लोग बीमार, पुलिस ने शुरू की जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान कथित रूप पर कुटू का आटा खाने से लगभग 200 लोग भोजन विषाक्तता के कारण बीमार पड़ गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर सहित विभिन्न इलाकों के मरीजों की हालत स्थिर है और कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया। पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग छह बजकर 10 मिनट पर जहांगीरपुरी थाने में उन्हें कई लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी, जिन्होंने कथित तौर पर कुटू के आटे से बना खाना खाया था। पुलिस ने बताया, टीम को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (बीजेआरएम) अस्पताल भेजा गया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सुबह से लगभग 150 से 200 लोग आपातकालीन वार्ड में रिपोर्ट कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध भोजन विषाक्तता ने इलाके में विशेष रूप से चिंता पैदा कर दी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के अवसर पर उपवास कर रहे हैं।

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जल्द होगा दीदार
नई दिल्ली (एजेंसी)। वंदे भारत ट्रेन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से स्लीपर कोच के साथ पर्यियों पर दौड़ सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिद्दु ने मंगलवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण किया जा चुका है। इसके एक रैक का निर्माण हो चुका है और दूसरे के निर्माण का कार्य जोर-शोर से चल रहा है और उम्मीद है 10 अक्टूबर तक इसके निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चूँकि इस ट्रेन को जोड़ी के रूप में चलाया होगा, इसलिए दूसरे रैक के निर्माण के बाद इसका रूट तय किया जाएगा और फिर इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने हालांकि इसके निश्चित समय और मार्ग के बारे में कुछ नहीं बताया है।

अगले तीन वर्षों में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल होगा:शाह

अहमदाबाद (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि पिछले एक दशक में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 91 से बढ़कर 38 हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले तीन वर्षों में भारत शीर्ष 10 में शामिल हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया अभियान के परिणाम दिखने लगे हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और इसने देश के युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाला बना दिया है। गुजरात सरकार के

स्टार्टअप कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक की घोषणा की गई

क्षमताओं को देखते हुए, दुनिया में नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की प्रमुख पहल है।जिसे



2016 में नवाचार को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिससे भारत को नौकरी चाहने वाले देश से नौकरी देने वाले देश में बदला जा सके। अमित शाह ने कहा, 2014 में हमारे पास केवल 510 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ 1.92 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं। 2014 में हमारे पास चार 'युनिर्कोन' थे और अब हमारे पास 120 ऐसे प्रतिष्ठान हैं। जिनका संयुक्त बाजार मूल्य 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

'उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे'

संजय राउत का भाजपा पर तंज

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला। उन्होंने सवाल उठाया कि आप देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर उपराष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त तक को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं? राउत ने कहा कि इस पूरे मामले पर किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है और यही भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। राउत ने कहा कि भाजपा नेतृत्व आज संगठनात्मक चुनाव कराने में असमर्थ

दिख रहा है। उन्होंने व्यंग्य किया कि जब सरकार सर्वोच्च संस्थानों के पदाधिकारियों को बदलने में सक्षम है, तो अपने संगठन प्रमुख के चुनाव से क्यों पीछे हट रही है। राउत के इस बयान को भाजपा की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सीधा हमला माना जा रहा है। मुंबई नगर निगम चुनाव की चर्चा मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे पर केवल तभी बयान दिया



जाएगा जब सारी चर्चाएं पूरी होंगी। राउत ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का असर बरकरार है और इसका प्रभाव आगामी चुनाव में दिखेगा। मराठी पहचान और ठाकरे ब्रांड राउत ने मराठी अस्मिता को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि 'मराठी जनता

दिखाएगी कि ठाकरे ब्रांड का असली मतलब क्या है।' उनका इशारा इस ओर था कि मुंबई और महाराष्ट्र में स्थानीय पहचान की राजनीति एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकती है। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच तालमेल की संभावना को लेकर भी उन्होंने उत्सुकता बढ़ाई। हालांकि माना जा रहा है कि राउत का यह बयान भाजपा पर दबाव बनाने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

दिल्ली में पोस्टर चिपकाना पड़ेगा महंगा: सीएम की चेतावनी, दीवार गंदी की तो होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में चल रहे स्वच्छता अभियान के बीच, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने मंगलवार को सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। एएनआई से बात करते हुए, सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिन में की गई घोषणा का स्वागत किया। सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों से कहा गया है कि वे दिल्ली की दीवारों को साफ-सुथरा और अच्छी तरह से बनाए रखें ताकि यह साफ-सुथरी दिखे। इस संबंध में, मुख्यमंत्री ने कहा



खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यह एक अच्छी पहल है और बहुत जरूरी भी है। इस बीच, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेंद्र

सचदेवा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 33 जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने नागरिकों से शहर को साफ रखने का आग्रह किया। सचदेवा ने एएनआई को बताया, स्वच्छता अभियान के तहत, आज हम दिल्ली के सभी नागरिकों और हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर 33 जगहों पर दिल्ली को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए; दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी- आधी क्षमता पर काम कर रहे हाईकोर्ट से तेज निपटारे की नहीं की जा सकती उम्मीद



उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आते, और जब वे अपनी आधी क्षमता के साथ काम कर रहे हों तो उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे हर मामले को तेजी

से निपटाएं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 13 साल पुराने मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उनका मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 साल से लंबित है। इस पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने स्पष्ट कहा, 'हाईकोर्ट इस अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के अधीन नहीं

है।' वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने पहले ही दो बार हाईकोर्ट में आवेदन देकर मामले के जल्दी निपटारे की गुहार लगाई है। इस पर पीठ ने कहा, 'आवेदन करना जारी रखें। अगर हाईकोर्ट आधी क्षमता के साथ काम कर रहा है तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हर मामले को तुरंत निपटाएं? उनसे पहले के कई पुराने मामले लंबित हैं। आप वहां जाकर निवेदन करें।' सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया

और याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह हाईकोर्ट में जाकर मामले की जल्द सुनवाई और निपटारे के लिए औपचारिक आवेदन करें। अदालत ने कहा कि ऐसे आवेदन पर हाईकोर्ट उचित तरीके से विचार करेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने वकील जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि वह लंबे समय तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं और वहां मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यह भली-भांति जानते हैं।





लखनऊ-बुधवार,24 सितम्बर 2025

रेलवे आडिटोरियम,गोरखपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों के साथ महाप्रबन्धक उदय बोरवणकर, अपर महाप्रबन्धक विनोद कुमार शुक्ला तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी संजय सिंहल

गोरखपुर,: महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर के मुख्य आतिथ्य में रेलवे प्रेक्षागृह,गोरखपुर में 23 सितम्बर,2025 को राजभाषा सप्ताह के अन्तिम दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ महाप्रबन्धक श्री बोरवणकर ने दीप प्रज्वलित कर एवं मौं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबन्धक श्री विनोद कुमार शुक्ल, प्रमुख विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं काव्यप्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबन्धक बोरवणकर ने कहा कि हिन्दी दिवस न के वल हिन्दी अपितु समस्त भारतीय भाषाओं का दिवस है और देश की गौरवशाली परम्परा का प्रतिचायक भी है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में रेल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 का समादर करते हैं और रेलवे अपने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में राजभाषा हिन्दी



महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि गोरक्षनगरी की अपनी अलग साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गरिमा रही है। यह नगर अनेक महान साहित्यकारों की कर्मभूमि और उनकी अमूल्य कृतियों की धरोहर रही है। इस रेल पर हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, नरेंद्र कोहली एवं राजेन्द्र यादव जैसे नामचीन लोग पधार चुके हैं। कलम के धनी इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में

युगान्तकारी परिवर्तन लाये हैं। इस कवि सम्मेलन में साहित्य के विविध

रसों के कवियों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मंचासीन कवि अपनी काव्य रचना से हमारे रेलकर्मियों के अन्दर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। स्वागत करते हुये मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री संजय सिंहल ने कहा कि राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आज यह कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऐसे आयोजनों से कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के प्रति

जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे अपने कार्यक्षेत्र में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के प्रति निरन्तर सजग है। सरकार की राजभाषा नीति हिन्दी भाषा के सरल और बोलचाल की भाषा को प्रोत्साहित करने वाली है। भारत के सामासिक संस्कृति को आत्मसात करते हुये हम अपने कार्यालयी कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के लिये निरन्तर सजग बने हुये हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कविगणों ने अपनी कविताओं की इन्द्रधनुषी छटा बिखेर कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज का यह कवि सम्मेलन श्रोताओं का मनोरंजन करने में सफल सिद्ध हुआ है। मेरठ से पधारी कवयित्री डा0 शुभम त्वागी ने मौं सरस्वती की वन्दना-मान करूँ सम्मान करूँ माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूँ माँ से कवि सम्मेलन आरम्भ किया। उन्होंने अपनी रचना कोई नगमा गुनुगुनाना अच्छा लगा, तेरा रूठना मनाना

अच्छा लगा हम तो चले आये तेरी एक मुस्कराहट पर, तेरे शहर में आना अच्छा लगा प्रस्तुत किया जिसे सभी ने सराहा। प्रतापगढ़ से पधारी श्रृंगार रस की कवयित्री सुश्री प्रीती पाण्डेय ने अपनी कविता- मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में घूम लेती हूँ याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ से सभी का मन मोह लिया। बलिया से आये कवि विनोद कुमार शुक्ल, मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संजय सिंहल, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी मोहम्मद याकूब शेख, गोरखपुर नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं निगमों के प्रमुख/ प्रतिनिधि तथा राजभाषा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर ने अपनी प्रस्तुति दी। बैठक को सम्बोधित करते हुये महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने सभी को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं देते हुये कहा कि 14 सितम्बर,1949 को संविधान सभा द्वारा हिन्दी को संघ संस्कार की राजभाषा के रूप

गोरखपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म की सफाई करते हुए स्वच्छताकर्मी

गोरखपुर, : रेल यात्रियों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध करणे



के उद्देश्य से 17 सितंबर से 02 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के सातवेंदिन 23 सितम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर मंडलों के प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं स्टेशनों पर प्लेटफार्म, सकुलेंटिंग एरिया, प्रतिकालय, कार्यालयों तथा ट्रेक के किनारों की सफाई की गई तथा स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर यात्रियों एवं कर्मचारियों को जागरूक किया गया। 23 सितम्बर, 2025 को लखनऊ मंडल पर लखनऊ जं., गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, खलीलाबाद, ऐशबाग

गयी। पर्यावरण संरक्षण के क्रम में प्लास्टिक के पूर्ण निषेध से सम्बन्धित बैनर एवं पोस्टरों के माध्यम से एक जागरूकता रैली निकाली गयी। गोण्डा रेलवे कालोनी में रेलकर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गयी। विभिन्न स्टेशनों पर सुखे एवं गीले कचरे के पृथक्कीकरण हेतु डस्टबिन का प्रावधान किया गया। वाराणसी मंडल पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अनर्गत आजमगढ़, बलिया, बनारस, वाराणसी सिटी, गाजीपुर सिटी, भटनी, छपरा, सीवान, देवरिया सदर, मऊ एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाकर कर्मचारियों एवं

यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा स्टेशनों पर सुखे एवं गीले



कचड़े के पृथक्कीकरण हेतु स्टेशनों पर अतिरिक्त डस्टबिन का प्रावधान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा भटनी, गाजीपुर सिटी एवं वाराणसी स्टेशनों पर वाटर बूथ पर पानी की गुणवत्ता की जाँच एवं फूड स्टालों का निरीक्षण किया गया तथा खाने-पीने वाली वस्तुओं को स्वच्छ बनाये रखने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये। पर्यावरण संरक्षण हेतु चिन्हित स्थानों पर पौधारोपण किया गया। स्टेशनों पर कार्यरत अनुबन्ध कर्मचारियों एवं रेलकर्मियों के साथ स्वच्छता सम्बन्धित नारों, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता रैली

निकाली गई। इज्जतनगर मंडल पर लालकुआं, काशीपुर, रूद्रपुर सिटी,



कन्नौज, काठगोदाम, हल्द्वानी तथा बरेली सिटी स्टेशनों पर सुखे एवं गीले कचड़े के पृथक्कीकरण हेतु स्टेशनों पर अतिरिक्त डस्टबिन का प्रावधान किया गया तथा प्लेटफार्मों, प्रतिकालयों, कार्यालयों, सकुलेंटिंग एरिया एवं ट्रेक के दोनो किनारों की सफाई की गयी। काशीपुर स्टेशन पर प्पैस्टिक के उपयोग को कम कसे के लिए यात्रियों एवं कर्मचारियों को इको प्रेंडली जूट के थैलों का वितरण किया गया। स्टेशनों पर कार्यरत अनुबन्ध के कर्मचारियों एवं रेलकर्मियों के साथ स्वच्छता सम्बन्धित नारों, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता रैली निकाली गई।

वाराणसी में नाविक समाज का विरोध प्रदर्शन, दशाश्वमेध घाट पर काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश

वाराणसी। में नाव संचालन पर रोक लगाने से नाराज नाविकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि प्रशासन द्वारा 72 दिन बाद भी नावों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। वाराणसी में प्रशासन के रवैये से नाराज नाविक समाज ने मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर नावों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में नाविक एकजुट होकर घाट पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान नाविक समाज के लोगों को समझाने के लिए एडीसीपी काशी टी सरवरण रविदास घाट पहुंचे। नाविक समाज के प्रतिनिधि प्रमोद माझी ने बताया कि 72 दिन बाद नाव संचालन

शुरू हुआ था, लेकिन प्रशासन ने बहाना बनाकर उस पर फिर से रोक लगा दी। उनका कहना है कि प्रशासन घाटों पर रोशनी की कमी का हवाला देता है, जबकि नाव संचालन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही होता है और उस समय पर्याप्त रोशनी रहती है। नाविकों ने यह भी कहा कि घाटों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी प्रशासन और नगर निगम की होती है, लेकिन गंगा की स्वच्छता और सफाई वे खुद करते हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की समस्या न हो। इसके बावजूद प्रशासन नाव संचालन के लगातार अड़चनें पैदा कर रहा है। प्रमोद माझी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों का कहना है कि 25 सितंबर को



निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद आदेश जारी होगा, लेकिन इस तरह समय निकालकर नाविक समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर क्रूज का संचालन लगातार जारी है और उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं डाली जा रही है। नाविक समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी माँग नहीं मानी गई तो वे कार्तिक पूर्णिमा

पर नाव संचालन पूरी तरह बंद कर आंदोलन को और आक्रामक रूप देंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रूज संचालन का घेराव करने की भी घोषणा की। इस विरोध प्रदर्शन में रामनगर से लेकर नमो घाट तक के सैकड़ों नाविक शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया।

खड़े ट्रेलर से टकराया ऑटो, तीन माह की बच्ची की मौत, छह लोग गंभीर रूप से घायल



चंदौली। के चंदौली जिले में मंगलवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें छह माह की बच्ची की मौत हो गई। वहीं छह लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। चंदौली जिले में मंगलवार की भोर

में रामनगर रोड पर कटेसर गांव के समीप एक भीषण हादसा हो गया। दाह संस्कार से लौट रहे परिजनों से भरा ऑटो खड़े ट्रेलर में जा टकराया। हादसे में तीन माह की बच्ची रिचा की मौके पर मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल

हो गए। सभी घायलों को पहले रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। कैसे हुआ हादसा चकिया के मांगरोर गांव में सोमवार को एक महिला की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर करने के बाद परिजन निजी ऑटो से घर लौट रहे थे। भोर में करीब चार बजे जैसे ही ऑटो कटेसर गांव के समीप रामनगर रोड पर पहुंचा, सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में बैठे सभी यात्री बुरी तरह फंस

गए और चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और आनन-फानन जलीलपुर पुलिस को सूचना दी। चौकी प्रभारी अभिषेक शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ऑटो और ट्रेलर को कब्जे में लेकर चौकी पर पहुंचा दिया। हादसे में ये लोग हुए घायल हादसे में कबीर दास (40), बेबी (36, पत्नी मोहित प्रसाद), आनंद (06, पुत्र मोहित प्रसाद), वैशाली (14, पुत्री मोहित प्रसाद), शशि (45, पत्नी मुकेश), संजय (41, पुत्र मुन्नीलाल) घायल हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुये महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर

गोरखपुर,: पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकस), गोरखपुर की बैठक 23 सितम्बर, 2025 को महाप्रबन्धक सभाकक्ष, गोरखपुर में आयोजित की गई। बैठक में अपर महाप्रबन्धक श्री विनोद कुमार शुक्ल, मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संजय सिंहल, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी मोहम्मद याकूब शेख, गोरखपुर नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं निगमों के प्रमुख/ प्रतिनिधि तथा राजभाषा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर ने अपनी प्रस्तुति दी। बैठक को सम्बोधित करते हुये महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने सभी को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं देते हुये कहा कि 14 सितम्बर,1949 को संविधान सभा द्वारा हिन्दी को संघ संस्कार की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ह्रदिन्दी दिवसद्व के उ्पलक्ष्य मेंकेन्द्र संस्कार के कार्यालयों/ बैंकों, उपक्रमों एवं निगमों में राजभाषा सप्ताह अथवा राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है। सुखद संयोग है कि आज कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयन्ती है तथा मुख्यालय में 18 सितम्बर से 23 सितम्बर,2025 तक राजभाषा सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हिन्दी राष्ट्रीय अस्मिता तथा सांस्कृतिक स्वाभिमान से देश को एक सूत्र में पिरोने की सशक्त कड़ी है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और देश की उन्नति के सपने देखे थे। इन सपनों को साकार करने में अन्य कारकों के साथ-साथ हिन्दी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हिन्दी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर गांधीनगर,जुगत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को हिन्दी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए

प्रशंसनीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज तकनीकी का युग है। दैनिक कार्यों में डिजिटलाइजेशन के तहत समस्त कार्यालयी कार्य हिन्दी में किया जाना है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963 के साथ-साथ सभी संवैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सुव्यवित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें। इन प्रयोजनों के लिये उपयुक्त और प्रभावकारी जांच बिन्दु बनायें और उपाय करें। इस दिशा में आप सब निरन्तर अपना प्रयास करते रहें। कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने का अनुकूल माहौल बना रहे, इसकेलिये ईमानदार प्रयास जरूरी है। महाप्रबन्धक ने कहा कि चीन में सभी कार्य वे अपनी भाषा में करते हैं, जबकि हम अपनी भाषा को हिन्दी में कुछ दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं।

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल द्वारा इस परियोजना का 26 सितम्बर, 2025 को निरीक्षण किया जायेगा

गोरखपुर,: संरक्षित, सुरक्षित एवं यात्रियों के मांग के अनुरूप ट्रेनों का सुगम परिचालन हेतु भारतीय रेल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इसी क्रम में, गोरखपुर जं.-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण की कमीशनिंग के परिप्रेक्ष्य में नॉन-इंटरलॉक कार्य प्रगति पर है। रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल द्वारा इस परियोजना का 26 सितम्बर, 2025 को निरीक्षण किया जायेगा। गोरखपुर जं.-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन निर्माण के अन्तर्गत किये जा रहे नॉन-इंटरलॉक कार्य के परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक के दौरान लखनऊ मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं खंडों पर विभिन्न कार्य सम्पादित किये गये, जिससे समय के साथ ही साथ ट्रेनों के संचलन को प्रभावित होने से बचाया जा सके। इस दौरान समारणों, प्वाइंट्स, आई.पी.एस., के.एल.सी.आर., एक्सल काउंटर, ब्लॉक इंस्ट्रुमेंट्स, सिगनल, एस.एम. पैनल तथा ट्रेक का अनुरक्षण किया गया। स्टेशनों के ई.एल.डी. फॉल्ट का रिकटिफिकेशन, स्टेशनों के पैनल टेस्टिंग, प्वाइंट को बदलने का कार्य, क्वाड केबल प्वाइंट, ब्लॉक खंडों में क्वाड केबल तथा स्टेशनों के सिगनलिंग केबल के मेजरिंग का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त रेल/स्लीपर की लॉडिंग/अनलॉडिंग की गई। कट कनेक्शन, टर्न आउट एवं ट्रेक की टैमिंग की गई। साथ ही 23 सितम्बर, 2025 को गोरखपुर जं. स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5/6 एवं 7/8 के मध्य फुट ओवर ब्रिज (एफ.ओ.बी.) का डिस्मेंटल किया गया, जिसमें 04 स्पैन एवं 03 स्तम्भों का डिस्मेंटल एवं डिलॉन्चिंग किया गया। इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु 02 अदद 140 टी.बी.डी. क्रैन, 02 अदद बी.एफ.आर. सेट (4 बी.एफ.आर. संरचना के साथ) एवं 02 टावर वैगन का उपयोग किया गया। गोरखपुर जं.-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण एवं गोरखपुर जं. स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज (एफ.ओ.बी.) के डिस्मेंटल कार्य में लगभग 250 विभागीय और संचिदा कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी कार्यों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है। तीसरी लाइन तथा दोहरीकरण निर्माण परियोजना का कार्य पूरा हो जाने से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी तथा मांग के अनुरूप अधिक संख्या में ट्रेनें तीव्र गति से चलाई जा सकेंगी। यात्री ट्रेनों का संचलन और अधिक सुचारू रूप से होगा तथा ट्रेनों के समय पालन में सुधार होगा, जिससे यात्रियों के यात्रा समय में बचत होगी। इसके साथ ही इस रेल खंड पर चलने वाली मालगाड़ियों के संचलन समय में भी कमी आयेगी, जो व्यापारियों/उद्यमियों के लिये काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

पूछताछ के उपरान्त उक्त लड़के को चाइल्ड लाइन, गोण्डा को सुपुर्द किया गया

गोरखपुर,: रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा, अवैध सामानों की धर-पकड़, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बचपन बचाओ अभियान के तहत मानव तस्करी की रोकथाम का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में, 22 सितम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोण्डा को निगरानी के दौरान स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 2 पर 06 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला। पूछताछ के उपरान्त उक्त लड़के को चाइल्ड लाइन, गोण्डा को सुपुर्द किया गया। 22 सितम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोरखपुर को निगरानी के दौरान स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 05/06 पर 13 वर्ष एक लड़का मिला, जिसे पूछताछ के उपरान्त चाइल्ड लाइन, गोरखपुर को सुपुर्द किया गया। 22 सितम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वाराणसी सिटी को निगरानी के दौरान स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 1 पर 19 वर्ष की एक युवती लावारिस हालत में मिली, जिसे वाराणसी सिटी पोस्ट पर लाया गया। पूछताछ के उपरान्त युवती के परिजन के पोस्ट पर उपस्थित होने पर युवती को सुपुर्द किया गया। 22 सितम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, गाजीपुर सिटी को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 19037 में यात्री का छूटा बैग मिला, जिसे कप्तानगंज पोस्ट पर जमा किया गया। 22 सितम्बर, 2025 को यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त बैग सुपुर्द किया गया। 22 सितम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ऐशबाग को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 22538 में यात्री का छूटा बैग मिला, जिसे ऐशबाग पोस्ट पर जमा किया गया। यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त बैग सुपुर्द किया गया। 21 सितम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लखनऊ जं0 को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 12534 में यात्री का छूटा बैग मिला, जिसे लखनऊ जं0 पोस्ट पर जमा किया गया।



एसएंडपी ने मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5■ पर बरकरार रखा

नई दिल्ली, रेंटिंग एजेंसी एसएंडपी को इस वित्त वर्ष में आरबीआई की ओर से 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने प्वानुमान को घटाकर ३.2 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए एजेंसी ने 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
एसएंडपी ग्लोबल रेंटिंम्स ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेंटिंग एजेंसी ने मोटे तौर पर अनुकूल रहे मानसून के बीच मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए यह अनुमान लगाया है।
एसएंडपी ने यह भी कहा कि उसे इस वित्त वर्ष में आरबीआई की ओर से 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने प्वानुमान को घटाकर ३.2 प्रतिशत कर दिया है।

आजम खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, दोनों दलों की 2027 में हार तय: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई के बाद उनके बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की हार तय है। सपा नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान विभिन्न आपराधिक मामलों में लगभग दो साल बाद जमानत मिलने के पश्चात मंगलवार को सीतापुर जिला कारागार से रिहा हुए। सीतापुर जिला कारागार के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सपा नेता आजम खान की रिहाई हो गई है। इस बीच, केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया, मोहम्मद आजम खान चाहें सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा-बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है।

दूसरे धर्मों में गईं बहनों की घर वापसी करावाएंगे,नवरात्रि में नव दुर्गा टास्क फोर्स का गठन
लखनऊ (संवाददाता)। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लोगों ने नवदुर्गा टास्क फोर्स ज्वाइन किया है। टास्क फॉर्स का उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना है। इसके लिए विध्व हिंदू रक्षा परिषद ने कार्डसॉलिंग सेंटर शुरू किया है। सनानी बहनें जो दूसरे धर्म में चली गई हैं। हम उनकी घर वापस कराएंगे। यह कहना है कार्तिक माथुर का। इन्होंने नव दुर्गा टास्क फोर्स की सदस्यता ली है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने नवरात्रि से धार्मिक कार्डसॉलिंग सेंटर शुरू किया है। वहीं 9 महिलाओं को कलावा बांधा कर नवदुर्गा टास्क फोर्स का गठन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे।

भाई ने बहन के प्रेमी को मार डाला,शादी की बात के बहाने घर बुलाया, दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या

ले जाया गया। अली के परिवार में तीन बहनें और एक भाई है। पिता अरिफ जमीर ईरिक्षा चलाते हैं। अरिफ जमीर ने बताया अली और युवती ने कुछ समय पहले शादी की इच्छा जाहिर की थी। इसी सिलसिले में बातचीत करने अली युवती के घर गया था। मृतक के जीजा कासिम ने बताया अली अब्बास को शादी की बात करने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान पीछे से सिर पर वार किया। अली जब खून से लथपथ होकर गिर गया तो आरोपी मौके से भाग गए। लड़की ने घरवालों को फोन पर सूचना दी। इसके बाद अली को अस्पताल ले जाया गया। लड़की ने अपने भाइयों के खिलाफ पुलिस के सामने बयान दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। मृतक पर सआदतगंज थाने में मारपीट के दो मुकदमे दर्ज हैं। मृतक के भाई अस्तर पर भी 4 मुकदमे हैं। भाई जेल में बंद है।

आशा वर्कर, सी एच ओ, कम्प्युनिटी फार्मैसिस्ट के समर्थन से दवाओं का दुष्प्रभाव रिपोर्ट करना होगा आसान: सुनील यादव

लखनऊ (संवाददाता)। आशा वर्कर, सी एच ओ, कम्प्युनिटी फार्मैसिस्ट के समर्थन से दवाओं का दुष्प्रभाव रिपोर्ट करना आसान और प्रभावशाली हो सकेगा। इसी के साथ सभी चिकित्सालयों को फर्माकोविजिलेंस के लिए सतर्क होना मरीजों की जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य है।
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के निर्देशन में औषधियों के प्रतिकूल प्रभाव को रिपोर्ट करने की संस्कृति का निर्माण करने हेतु फार्मैसिस्ट फेडरेशन द्वारा किए गए अपील पर पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए , जिसका समापन आज ए्टा में आयोजित वेबिनर में किया गया, जिसमें फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन एवं फार्मैसिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव द्वारा अपना व्याख्यान देते हुए यह अपील की गई।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र के निर्देशन में विभिन्न कर्मचक संग्पन हुए। इसके पूर्व विभिन्न संस्थानों के साथ प्रदेश सरकार के एफ एम रेडियो और आकाशवाणी सहित अनेक चैनलों पर वाताां प्रसारित की गई।
इकल प्रयागराज में एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसमें मंडल के फार्मैसिस्ट शामिल थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अध्यक्ष विश्वियालय में आयोजित वेबिनार को भी श्री सुनील यादव के साथ निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र, प्रो विजय , प्रो अजय शुक्ला, प्रो विष्णु,प्रो कुणाल ने भी संबोधित किया।
जनता को यह बताने का प्रयास किया गया कि यदि कोई भी दवा गलत प्रतिरक्षा देती है तो टोल फ्री नंबर 1800-180-3024 या पीवीपीआई की वेबसाइट पर रिपोर्ट करिए।
कोई भी स्वास्थ्य प्रदाता या मरीज स्वयं यह रिपोर्ट कर सकता है। इसमें मरीज की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है।
यह मरीजों की सुरक्षा के लिए प्रभावी हथियार होगा।

बिजली निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन,विद्युत कर्मचारियों ने अधिकारियों को घेरा

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में विद्युत कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से अपील की है कि वे आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मदद से पवार कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए निजीकरण के संशोधित आरएफबी डॉक्यूमेंट को मंजूरी न दें। संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा- निजीकरण के प्रस्ताव से कर्मचारियों में नाराजगी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 300 दिन पूरा होने पर लखनऊ में शक्ति भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा। इसमें बिजली कर्मी, सॉिदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अधिकारी शामिल हैं। संघर्ष समिति ने कहा नवरात्र और रामलीला पर बिजली आपूर्ति बाधित न हो। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उग्र के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की प्रक्रिया में आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की पूरी दखलंदाजी चल रही है। निजीकरण का संशोधित आरएफबी डॉक्यूमेंट निजी घरानों की मिली भगत से डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा तैयार किया गया है, जिससे पहले से तय निजी घरानों को लाभ पहुंचाया जा सके। संघर्ष समिति ने गोरखपुर और बस्ती क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी मेसर्स जीनस द्वारा विभाग के द्वारा रिजकटेड लिस्ट को अभियंताओं की आंखी से छेड़छाड़ कर 17 सितंबर की आधी रात में अपूर करने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

सरकार बननेपर आजम खान के मुकदमे वापस होंगे: अखिलेश

कहा यह लोग जीएसटी को नहीं समझते हैं। जिनको जीएसटी की कोई जानकारी नहीं। वह लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने वाले लोग कह रहे हैं कि 50: कीमत कम हो गई। यह लोग बताएं कि जो मुनाफा कमा रहे हैं उससे महंगाई नहीं बढ़ी है। क्या भ्रष्टाचार से महंगाई में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिस तरह भाजपा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मुकदमे वापस लिए और अपने

कहा जबतक राजनीति में रहेंगे। इन्हीं का सिला पहनेंगे। नेताजी के कपड़े भी इसी दुकान में सिले जाते थे। सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए न्यायालय को धन्यवाद कहा। सीतापुर में गाड़ियों के सपा कार्यकर्ताओं के गाड़ियों पर हुए चालान पर बोले सपा झंडे के साथ पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का भी चालान कर देंगे। अखिलेश यादव ने

यादव मंगलवार को हजरतगंज स्थित जनपथ मार्केट पहुंचे थे। यहां कपड़ों की दुकान का उद्घाटन किया। उनके साथ इंदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी थे। दुकान के उद्घाटन के बाद अखिलेश यादव ने शेरवानी का नाप दिया। उन्होंने कहा पहली बार कुर्ता और शेरवानी इन्हीं के यहां से मेरे लिए सिलाई गई थी। 48 घण्टे में इन्होंने हमारी यूनिफ शेरवानी तैयार की थी। उन्होंने

लखनऊ-बुधवार,24 सितम्बर 2025

लखनऊ

दीपोत्सव: दीवाली पर रेशन होगी अयोध्या,देव दीपावली पर काशी

दीपावली में अयोध्या में जलेंगे 26 लाख दीप,देव दीपावली पर वाराणसी के घाटों पर जलेंगे 10 लाख



लखनऊ/अयोध्या (संवाददाता)। दीपोत्सव में अयोध्या जगमगाएगी तो देव दीपावली में काशी के घाट जगमगाएंगे। वाराणसी में इस बार देव दीपावली के मौके पर भव्य उत्सव मनाए जाने की तैयारी है। 5 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों पर 10 लाख से अधिक दीये अर्धचंद्राकार घाटों को रेशन करेंगे। 5 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों पर 10 लाख से अधिक दीये

अर्धचंद्राकार घाटों को रेशन करेंगे। इन 10 लाख दीयों में एक लाख दिदि गाय के गोबर से बने होंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे। माना जा रहा है कि वाराणसी के घाटों पर होने वाले इस दिव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों भक्त और पर्यटक जमा होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए घाटों पर रेशनी की आकर्षक व्यवस्था की जाएगी और साज-सजावट के साथ विशेष स्वच्छता

फेडरेशन अफ उत्तर प्रदेश कैटरर्स की हुई शुरुआत, कैटरिंग उद्योग को मिलेगा नया आयाम

लखनऊ (संवाददाता)।उत्तर प्रदेश के कैटरिंग पेशेवरों को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैटरर्स की स्थापना हो गई है। अध्यक्ष तरुण साहनी ने बताया कि 40एड50 वर्षों के अनुभव रखने वाले वरिष्ठ उद्योग विशेषज्ञों द्वारा गठित यह संगठन कैटरिंग क्षेत्र को शिक्षा, सहयोग और संरचित हाहायता के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेगा। सचिव सुधीर टंडन ने बताया कि हमारा संगठन कैटरिंग की मूलभूत बातें, टैक्सेशन, बजटिंग और कॉस्टिंग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देने का काम करेगा। कोषाध्यक्ष काजी अख्तर मसूद ने कहा कि कैटरर्स और उनके सहयोगी विक्रेताओं के बीच तालमेल को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। यह संगठन प्रमुख लक्ष्य राज्यभर के कैटरर्स को नियामक समर्थन और संरक्षण उपलब्ध करायेगा। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि कैटरिंग सेवाओं के समापन के लिए एक संरचित समयसीमा तय हो, जिससे कर्मचारियों के हित और स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके।व्यावसायिक विकास के साथ-साथ महासंघ ने सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है।

जीएसटी रिफर्म जागरूकता अभियान के अंतर्गत हलवासिया मार्केट में आयोजित हुआ व्यापारी संवाद कार्यक्रम, दिनेश शर्मा ने व्यापारियों से किया संवाद

लखनऊ (संवाददाता)। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने जी एस टी रिफर्म जागरूकता अभियान के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में हलवासिया मार्केट हजरतगंज मे उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में आयोजित प्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी सुधार के अंतर्गीत घटी दर को लेकर चर्चा की तथा उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने के साथ हलवासिया मार्केट में पैदल चलकर दुकान दुकान जाकर व्यापारियों व ग्राहकों से जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया जानी उन्होने कारोबारियों से अप्रग्रह किया कि जीएसटी का लाभ ग्राहकों को अवश्य प्रदान करें तथा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावे के लिए प्रतिष्ठानो परु हम सबने ये ठाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ष्हर घर

व्यापार एवं उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा नवरात्रि एवं दीपावली के अवसर पर जीएसटी की दरें घटाए जाने से इस वर्ष त्योहारी सीजन मेंपिछले वर्ष की तुलना में 40: से 50: तक व्यापार में ग्रोथ होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने स्वदेशी उत्पाद बेचने एवं निजी जीवन में प्रयोग करने का निर्णय लिया है। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में घरेलू माँग बढ़ने की पूरी उम्मीद है।जिससेएमएसएमईसेक्टर भी मजबूत होगा तथा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी उन्होंने प्रशानमंत्री एवं वित्तमंत्री को धन्यवाद ज़ापित किया व्यापारी संवाद

लोकल फर वोकल पर केन्द्रित प्रगति महोत्सव -2025 आज से

लखनऊ (संवाददाता)। प्रगति इवेंट के तत्वावधान में 24 सितम्बर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रगति महोत्सव-2025 का आयोजन सेक्टर-एम, आशिषाना लखनऊ (आशिषाना गुरुद्वारे के बगल) में होगा। इस बात की जानकारी आज कार्यक्रम स्थल पर प्रगति इवेंट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रगति महोत्सव-2025 वोकल फर लोकल और स्वदेशी अपनाओ पर केन्द्रित है। इस महोत्सव में प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प, देशी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, हैण्डलूम- हैण्डी क्राफ्ट, खादी, इलेक्ट्रॉनिक के

समान, सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का सिलारन, गर्म कपड़े, शाल, बनारसी सड़िया व लहंगे, कानपुर का चमड़े का सामन, घरेलू सामान और लघु इकाइयों द्वारा निर्मित अचार, पापड़, मसाले, क्रॉकरी, मेवे व अन्य सामानों के स्टाल होंगे। विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रगति महोत्सव में निःशुल्क प्रगति महोत्सव टैलेंट हण्ट-2025 का आयोजन किया जायेगा, इसके तहत बच्चों व युवाओं की गायन, नृत्य, वादन, किड्स मॉडलिंग , मेंहदी, रंगोली, कबाड़ से जुगाड़, सिलाई, चित्रकला, निबंध लेखन, साइकिल रेस, खो-खो, कबड्डी प्रतियोगिता का

का एक अधिकारी मिलकर आजम खान पर अन्याय नहीं करेंगे। आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा- आजम खान सपा के संस्थापक हैं। हमेशा नेताजी का और हमारा साथ दिया है। भाजपा से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुबानी दी है, उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। अखिलेश

संक्षिप्त खबरें

सिविल डिफेंस के नवनियुक्त डिप्टी डिविजनल

वार्डेन रामगोपाल सिंह का किया भव्य स्वागत

लखनऊ (संवाददाता)। निःस्वाथ सेवा भाव से निरंतर सामाजिक कार्यों एवं सिविल डिफेंस में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिक सुरक्षा प्रखण्ड राजाजीपुरम के नवनियुक्त डिप्टी डिविजनल वार्डेन रामगोपाल सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया और उनके उच्चल भविष्य को कामना की गई। सिविल डिफेंस क सेक्टर वार्डेन मुकेश कुमार निगम, मयंक कुमार श्रीवास्तव, डा. सत्य प्रकाश शर्मा, अभिनव खंडेलवाल, सोनम सिंह, विनय कुमार, जितेन अरोड़ा, शुभ-श्रीवास्तव, अमान खान, अमोघ लहरी, अमित वर्मा, रजत राजपूत, मीतू सिंह आदि ने शुभकामनाएं प्रेषित किया और नियंत्रक एवं जिलाधिकारी विशाखा जी, चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्रा, उपनियंत्रक रविन्द्र कुमार, डिप्टी चीफ वार्डेन गुरप्रीत सिंह सेठी, स्टफ ऑफिसर ऋतुराज रस्तोगी, वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक मनोज वर्मा, एडीसी मुकेश कुमार का आभार व्यक्त किया।

दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ा

लखनऊ (संवाददाता)। बाजार खाला इलाके में दबंगों की पीटई से युवक की आंख और सिर में गंभीर चोट आई है। दबंगों ने पहले युवक को कॉल करके घर के बाहर बुलाया। इसके बाद उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। रामनगर ऐशबाग धोबीघाट निवासी गिरिश शर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे उनके बेटे विशु शर्मा को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। इलाके के रहने वाले आरोपी शिवांश, अर्जुन, अजय और युवराज पहले फोन करके विशु को मिलने के लिए घर से बाहर बुलाया। विशु उससे मिलने पहुंचा, तो उस पर हमला कर दिया। लोहे की रॉड और हाथ में पहनने वाले कड़े से उसकी पीटई की। उसके सारे कपड़े फाड़ दिए और मोबाइल फोन तोड़ दिया। उसको धोबीघाट पर ले जाकर पीटा। दबंगों की पीटई से विशु की आंख में गंभीर चोट आई और सिर पर भी कई जख्म हुए। परिजनों का कहना है कि मारपीट के दौरान आसपास के लोग जमा हुए और उसे छुड़ाने की कोशिश की, तब भी दबंग उसकी पीटई करते रहे। बाद में भाग गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मोहल्ले वाले भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। घायल विशु का इलाज कराया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पेक्टर बाजार खाला का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।

किसान पथ पर ट्रक-पिकअप में भीषण टक्कर,चालक की मौत; केबिन को गैस कटर से काटकर शव को बाहर निकाला

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में किसान पथ पर ट्रक-पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप बुरी तरह पिचक गई और चालक का शव केबिन में फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गैस कटर से केबिन काटकर शव को बाहर निकाला गया है। हादसे की खबर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। इससे सड़क पर जाम लग गया। मृतक की पहचान हरदोई के सदरपुर बिलग्राम के रहने वाले 55 वर्षीय रमेश चंद्र राठौर के रूप में हुई है। वह पिकअप पर मिमरल वाटर बोतलें लोड कर डिलीवरी देने जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे माती अंडरपास के पास सामने से आ रहे ट्रक से पिकअप की टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल और पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया। इसके बाद गैस कटर से पिकअप का केबिन काटकर कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। उसे तुरंत ट्रॉपा सेंटर-टू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वाहन मास्टर और परिजनों को सूचना दी है। क्रेन की मदद से वाहनों का मलबा सड़क से हटवाकर वातायत व्यवस्था सुचारू की गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है।

राजकीय विभाग चालक संघ का चुनाव 5 अक्टूबर को होगा

लखनऊ (संवाददाता)। राजकीय वाहन चालक संघपि विभाग का चुनाव पूर्व प्रक्रिया और निर्वाचन अधिकारी मिनिस्टीरियल एसोसिएशन धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की देखरेख में होगा। इस आशय का निर्णय आसपास के पदाधिकारियों और महासंघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में लिया गया। इस आम सभा की अध्यक्षता राजकीय वाहन चालक महासंघ के अध्यक्ष रिजवान अहमद सिद्दीकी और संचालन गोपीचन्द्र यादव ने किया। पि विभाग चालक संघ की आमसभाकृषि मुख्यालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 25 की अधिवेशन/ चुनाव की अनुमति पत्र जारी किये जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि चुनाव पूर्व नामांकन प्रक्रिया एवं तय चुनाव अधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। खास बात यह कि यह पूरी चुनाव प्रक्रिया महासंघ के पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराई जाएगी। इस आम सभा में महासंघ के महामंत्री जयप्रकाश त्रिपाठी, चालक संघ वन विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम, विभागीय चालकों में अयोध्या प्रसाद पाण्डेय, राम लखन, सूरज कुमार,रविन्द्र प्रताप सिंह, गुलाब यादव, गिरिश पाण्डेय,राजेश कुमार सहित मुख्यालय के 95 प्रतिशत चालक मौजूद रहे।

अखण्ड आर्यावर्त आर्यमहासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने काली बाबा

लखनऊ (संवाददाता)। अखण्ड आर्यावर्त आर्य त्रिदण्डी महासभा ने कामाख्या, असम के काली बाबा को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। वहीं चेन्नई रमेश बाबू को तमिलनाडु और बेंगलुरु के सुरेश जैन को कर्नाटक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने आज यहां इस आशय की जानकारी देते हुये बताया कि संगठन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित दो राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती की और कदम बढ़ाया है। नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता काली बाबा एवं तमिलनाडु व कर्नाटक के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षों को शुभकामनायें देते हुये भरोसा जताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कालीबाबा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की बातों को प्रखर रूप से सामने रखेंगे। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में संगठन का विस्तार कर उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ संगठन में नयी जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु व कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्षों ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुये विश्वास दिलाया कि संगठन की नीतियों को आगे बढ़ायेंगे।

आरएम बरेली के खिलाफ मंत्री ने एमडी को लिखा पत्र

लखनऊ (संवाददाता)। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बरेली क्षेत्र दीपक चौधरी के भ्रष्टाचार में लिप्त एवं मनमाने ढंग से कार्य करने के मामले में प्राप्त शिकायत के आधार पर डा. अरुण कुमार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने प्रबंध निदेश सड़क परिवहन निगम का उक्त के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि इन्हीं के कारण पहले भी एक मामले में एमडी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा था। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन बरेली क्षेत्र दीपक चौधरी के भ्रष्टाचार में लिप्त एवं मनमाने ढंग से कार्य करने सम्बंधी प्राप्त का हवाला देते हुए मंत्री ने लिखा कि देशपाल, बुकिंग लिपिक बरेली क्षेत्र का चोरी की मोटरसाइकिल चालाने के सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है परन्तु क्षेत्रीय प्रबंधक ने निजी वित्तीय लाभ लेकर विभागीय कार्यवाही में उक्त कर्मचारी के प्रकरण का निस्तारण बिना दंड दिये,बिना न्यायालय की कार्यवाही का संचालन लिये कर दिया एवं दंडित, आरोपित कर्मचारियों को सहायक यातायात निरीक्षक बना दिया जो घोर भ्रष्टाचार का सूचक है। इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा भी कार्यवाही की गई है। अतः मैं कहना चाहूँगा कि उपरोक्त दीपक चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाये।



सम्पादकीय

जातिवाद पर प्रतिबंध

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक आदर्श समाज व्यवस्था निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, अपने राजनीतिक जीवन के अनेक उदाहरणों से समाज को सन्निय प्रशिक्षण भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने समाज में जाति आधारित विद्वेष को ही नहीं बल्कि विभेद को भी समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सद्भाव के साथ सबके विकास को बल देने का सुखबूझभरा फैसला लिया है। इस फैसले के अन्तर्गत उन्होंने जाति-आधारित रैलियों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति संबंधी उल्लेखों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक है। यह केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है। राजनीतिक दलों ने जाति आधारित वोटों को लुभाने एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने के लिये समाज को बांटा है। यह गौर करने की बात है कि जाति आधारित संगठनों और रैलियों की बाढ़ आ गई है, जिससे एक-एक जाति के अनेक संगठन बने और इन जातिगत संगठनों ने सड़कों पर उतर कर न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, ईसान-ईसान के बीच दूरियां-विद्वेष बढ़ा दिया बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी क्षत-विक्षत कर दिया। भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। जाति व्यवस्था ने कभी सामाजिक पहचान और श्रम विभाजन का आधार बनकर काम किया, लेकिन समय के साथ यह भेदभाव, असमानता और सामाजिक विद्वेष का कारण बन गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- ह्मजातिवाद समाज की आत्मा को खोखला करता है।ह्म डॉ. भीमराव आंबेडकर ने तो इसे भारतीय प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बताया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी जातिवाद ने राजनीति और समाज दोनों में पेट बनाई और देश की एकता को कमजोर करने का काम किया। जाति-आधारित राखनीति ने सत्ता के समीकरण तो बदले लेकिन समाज को बांटने का काम किया। चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरणों के आधार पर होता रहा। समाज के बंटवारे का यह खेल लोकतंत्र के स्वस्थ आदर्शों के लिए चुनौती बना। जातिगत रैलियां और प्रदर्शन सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते रहे। पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख अपराधी को अपराधी नहीं बल्कि किसी जाति का प्रतिनिधि बना देता था, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था। इन जटिल स्थितियों में योगी सरकार का यह निर्णय विषमताओं एवं विस्मृतियों को समाप्त करने की दिशा में एक नया अध्याय है। यदि इसे सख्ती और ईमानदारी से लागू किया गया तो निश्चित ही समाज में सौहार्द, भाईचारा और समानता का वातावरण बनेगा। जाति-आधारित पहचान की जगह व्यक्ति की योग्यता, आचरण और योगदान को महत्व मिलेगा। किसी जाति के प्रति लगाव दर्शाने के लिए किसी अन्य जाति को नीचा दिखाने की भी गलत परंपरा पड़ती दिख रही है। जाति आधारित पोस्टर या प्रतीक न केवल गलियों में, मकानों पर बल्कि अपने वाहनों पर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में, परस्पर भेद, ऊंच-नीच की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे भेद को मिटाने की मांग उठती रही है। समाज के लिए चिंतित रहने वाले लोग यही चाहते हैं कि जातिगत झंडों और पोस्टरों पर एक हद तक लगाम लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा साहस राजनीतिक स्वार्थों के चलते अब तक किसी भी राजनेता ने नहीं दिखाया, लेकिन योगी सरकार ने यह साहस दिखाया है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। योगी सरकार द्वारा जारी 10 सूत्रीय दिशा-निर्देश में यह बात विशेष रूप से गौर करने लायक है कि अब जाति के नाम, नारे या स्टिकर वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 19८८ के तहत चालान किया जाएगा। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जाति को दर्शाने से बचा जाएगा। अभी तक होता यह है कि अपराधी जाति के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं और मजबूत हो जाते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि विशेष रूप से चुनाव के समय जाति आधारित बैनरों की बाढ़ आ जाती है। राजनीतिक दल एवं नेता जातिगत समीकरणों से समाज को बांटने में जुट जाते हैं। लेकिन अब वृषी सरकार की मंशा सराहनीय है और इन दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। वाकई समाज से अपराध को मिटाने के लिए अपराधी की जाति देखना गैर-वाजिब है। हां, यह सावधानीपूर्वक कुछ मामलों में जाति का उल्लेख करने की दृष्ट दी गई है। जैसे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल होता रहेगा। वाकई, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जहां जाति की चिंता या उल्लेख जरूरी हो जाता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि जाति आधारित भेदभाव अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल जाता है।

अमेरिकी आत्मघाती वीजा बंदिशें, भारत के नये अवसर

अमेरिका और भारत के संबंध बीते दो दशकों में आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी सहयोग की नई ऊँचाइयों पर पहुंचे हैं। अमेरिका ने भारत को रणनीतिक साझेदार माना है। रक्षा, व्यापार और तकनीक में गहरे संबंध बने हैं और भारतीय प्रवासी अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के पेशेवरों, खासकर भारतीयों के सपनों पर एक नई काली छाया डाल दी है, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है एवं एक बड़ा संकट खड़ा दिया है। २१ सितंबर की रात १२ बजे के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वालों को एच१बी वीजा प्राप्त करने के लिए लगभग एक लाख डॉलर यानी करीब ८८ लाख रुपये सालाना शुल्क देना होगा। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रभाव-प्रवास और अमेरिका-भारत संबंधों पर गहरा प्रभाव डालने वाला कदम है। अमेरिका के इस कदम के बाद भारत को अपनी आत्म-निर्भरता, स्वदेशी भावना एवं देश की प्रतिभाओं का देश में ही उपयोग को बल देना होगा। भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने के साथ अवसरों की भूमि बन रहा है। इसलिये अमेरिका के निर्णय से ज्यादा प्रेशान होने की बजाय इसको सकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत है। निश्चित ही अमेरिका दशकों से अवसरों की भूमि माना जाता रहा है। यहां आने का सपना रखने वालों के लिए एच१बी वीजा एक सुनहरा टिकट एवं उन्नत जीवन का आधार रहा है। हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इस वीजा के माध्यम से अमेरिका जाकर अपने सपनों को साकार करते रहे हैं। सिलिकॉन वैली की चमक और वहां भारतीय प्रतिभाओं का पर्यस्च इसका जीता-जागता प्रमाण है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों में उच्च तकनीकी पदों पर भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति सर्वाधिक है। भारतीय आईटी पेशेवरों के बिना अमेरिकी तकनीकी जगत की कल्पना करना कठिन है। एच-१ बी वीजा की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि का फैसला भारतीय आईटी कंपनियों के साथ अमेरिकी हितों को भी चोट पहुंचाने वाला है। इनमें आइट्टी सेक्टर से इतर क्षेत्र की कंपनियां भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि उनके फैंसले की आलोचना अनेक अमेरिकी ही कर रहे हैं। यदि ट्रंप यह सोच रहे हैं कि एच-१बी वीजा धारकों की फीस एक हजार डालर

से एक लाख डालर सालाना करने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियां अमेरिका के युवाओं को नौकरी देने के लिए बाध्य हो जाएंगी तो यह उनकी भूल है, क्योंकि इन कंपनियों को जैसे और जितने सक्षम युवा पेशेवर चाहिए, वे अमेरिका में हैं ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति यह भी भूल रहे हैं कि अमेरिका के आर्थिक विकास में अप्रवासियों विशेषतः भारतीय प्रतिभाओं का सर्वाधिक योगदान है और यह केवल पेशेवर लोगों का ही नहीं, बल्कि कामगारों का भी है। भले ही ट्रंप



प्रशासन का यह आदेश उनकी ह्मअमेरिका फस्ट्ह नीति की अगली कड़ी है। उनका तर्क है कि विदेशी पेशेवर सस्ते श्रम के रूप में अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं। शुल्क इतना अधिक करके वे चाहते हैं कि केवल वही विदेशी पेशेवर अमेरिका आएं, जो न केवल उच्च योग्यता रखते हों बल्कि भारी शुल्क अदा करने की क्षमता भी रखते हों। लेकिन यह कदम अमेरिका के लिये ही आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को उच्च कौशल वाले पेशेवरों की भारी जरूरत है और भारतीय आईटी पेशेवरों की कमी वहां सीधे तौर पर नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगी। ट्रंप के फैसले को आपदा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। पहले भारतीय प्रतिभा अमेरिका की ओर बहती थी, अब यह प्रवाह कनाडा,

न्याय की रीढ़ पर वार: क्यों जरूरी है अधिवक्ता संरक्षण कानून

17 सितंबर की वाराणसी घटना के बाद २० सितंबर २०२५ को विधान परिषद सदस्य अशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने की माँग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी ठोस कदम नहीं उठाती तो अधिवक्ता समाज का धैर्य टूट जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग उत्तर प्रदेश में लगातार तेज हो रही है। हापुड़ से वाराणसी तक हूँ घटनाओं ने वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया है। विधि आयोग और बार काउंसिल अपनी सिफारिशें सरकार को दे चुके हैं। अब जरूरत है कि विधानमंडल तुरंत अधिनियम लागू कर न्यायपालिका की रीढ़ को मजबूती दे। लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में वकील समाज का अभिन्न हिस्सा है। अदालत की चौखट पर जब आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर

पहुँचता है, तो उसका सबसे बड़ा सहारा अधिवक्ता ही होता है। अधिवक्ता न केवल अपने पुनर्विक्रल का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्यायपालिका और जनसाधारण के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं। किंतु दुखद है कि जो र्ग कानून और व्यवस्था की रक्षा करता है, वही आज खुद असुरक्षित है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जुलाई २०२१ में हुई, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका मसौदा प्रस्तुत किया। इसमें अधिवक्ताओं को हिंसा, धमकी और उसीइन से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा के ठोस प्रावधान रखे गए। २०२२ में संसद की स्थायी समिति ने मसौदे की समीक्षा कर संशोधनों की सिफारिश की। इसके बाद मार्च २०२३ में रजस्थान पहला राज्य बना जिसने यह अधिनियम पारित कर अधिवक्ताओं को सुरक्षा का कवच दिया

और अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगाई। उत्तर प्रदेश में यह माँग २९ अगस्त २०२३ की हापुड़ घटना के बाद और तीव्र हो गई। उस दिन पुलिस ने न्यायालय परिसर में निहत्थे अधिवक्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। न्याय की रक्षा करने वाले स्वयं न्यायालय परिसर में ही अपमानित और घायल किए गए। यह दृश्य पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशनों को झकझोर गया और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग को और प्रबल बना दिया। इसके विरोध में ४ सितंबर २०२३ को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने तीन-दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और अदालतों में कामकाज ठप हो गया। हापुड़ घटना के बाद ५ सितंबर २०२३ को योगी सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का दायित्व था कि वह अधिवक्ताओं से सुझाव लेकर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार

करे और सरकार को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के संबंध में ठोस दिशा-निर्देश दे। ९ सितंबर २०२३ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए एक न्यायिक समिति गठित की। समिति को १६ सितंबर से बैठकें शुरू करने का निर्देश दिया गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस की बढ़ती दखलअंदाजी, मनमानी गिरफ्तारी और सुरक्षा की कमी की शिकायतें कीं। सितंबर के अंत तक ४० से अधिक शिकायतें मिलीं। अक्टूबर २०२३ में अंतिम रिपोर्ट में अधिवक्ताओं पर हमले को न्यायिक कार्यवाही में गंभीर बाधा बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार कर राज्य विधि आयोग को सौंपा। विधि आयोग ने नवंबर २०२३ में अपनी सिफारिशें दीं, जिनमें

अदालत परिसरों में सीसीटीवी के कैमरे लगाने, अधिवक्ताओं को सुरक्षित और पक्के चैंबर उपलब्ध कराने, सामूहिक बीमा योजना लागू करने और महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में उन्हें न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का सुझाव शामिल था। आयोग ने यह भी कहा कि किसी अधिवक्ता की गिरफ्तारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न हो और गिरफ्तारी की स्थिति में २४ घंटे के भीतर संबंधित बार एसोसिएशन को सूचना दी जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रारूप में अधिवक्ताओं पर हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर छह महीने से पाँच वर्ष तक की सजा और पचास हजार से दस लाख

रुपये तक का जुर्माना होगा, जबकि पुनरावृत्ति की स्थिति में यह सजा दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। अदालत को पीड़ित अधिवक्ता को मुआवजा देने का अधिकार होगा। लेकिन अधिवक्ता समाज को अपेक्षित परिणाम अब तक नहीं मिले। प्रथमराज ने अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला की दिनदहाड़े हत्या ने यह पर्येश दिका कि पेशेवर दायित्व निभाने वाले वकील भी असुरक्षित हैं। १७ सितंबर २०२५ को वाराणसी जिला न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ, जिसमें उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। लगभग ७० अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार किया और अदालतों का वातावरण तनावपूर्ण हो गया।

विदेशी निर्भरता घटाइए, राष्ट्रीय सफलता बढ़ेगी

प्रधानमंत्री मोदी की मानें तो किसी भी मामले में विदेशी निर्भरता से राष्ट्रीय स्वाभिमान को नुकसान पहुंचता है। जब देश अपनी जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होता है, तो उसका स्वाभिमान कमजोर पड़ता है। देश का विकास और फैसले बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों गुजरात के भावनगर में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अन्य देशों पर निर्भरता है और जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्रीय विफलता बढ़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि १४० करोड़ भारतीयों का भविष्य बाहरी ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। आत्मनिर्भरता देश के सभी समस्याओं का समाधान है और यही राष्ट्रीय सौभाग्य और विकास की कुंजी है। इससे साफ है कि २०२५ की अंतिम तिमाही से पहले चले अंतरराष्ट्रीय दांवपेचों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगाह कर दिया है कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्रीय विफलता होगी। ऐसा कहकर उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ तो उन्होंने चीन से आयात पर और अमेरिका को निर्यात पर या ऐसे ही अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त करनेकेलिए सोच और साधन दोनों बदलने का आह्वान किया है। वहीं, दूसरी

तरह विदेशी बहु समझी जाने वाली कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी और उनके पुत्र-पुत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विदेशी तिकड़मों से भी सावधान रहने के इशारे किए हैं, क्योंकि: उनका मुस्लिम प्रेम, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका प्रेम और राष्ट्रविरोधी ताकतों को सिपासी संरक्षण दे देश के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। चूंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और सोनिया गांधी-प्रियंका गांधी क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा के सांसद हैं। इसलिए इनकी हर कोशिशों पर देश-दुनिया की नजर रहती है। प्रधानमंत्री मोदी की मानें तो किसी भी मामले में विदेशी

निर्भरता से राष्ट्रीय स्वाभिमान को नुकसान पहुंचता है। जब देश अपनी जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होता है, तो उसका स्वाभिमान कमजोर पड़ता है। देश का विकास और फैसले बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों के

है। आत्मनिर्भरता की कमी के कारण देश अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और उद्योग, तकनीक, और नौकरियों का विकास रुक जाता है। इससे राष्ट्रीय विकास की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा, विदेशी निर्भरता से



खिलाफ हो सकते हैं। वहीं विदेशी निर्भरता से आर्थिक नुकसान और अस्थिरता पैदा होती है। विदेशी निर्भरता से देश की आर्थिक सुरक्षा कमजोर होती है। वैश्विक बाजारों या विदेशी साधनों पर निर्भरता से आर्थिक संकट आने पर देश प्रभावित होता है, जिससे विकास रुक सकता है। विदेशी निर्भरता से विकास भी बाधित होता

रणनीतिक खतरा भी बढ़ता है। सुरक्षा और महत्वपूर्ण संसाधनों में विदेशी निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होती है। आपातकाल में या भू-राजनीतिक तनाव में यह बड़ी समस्या बन सकती है। यही वजह है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई तरीकों और नीतियों पर काम कर रहा है। एक ओर भारत स्थानीय

विकास एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, ऊर्जा स्वतंत्रता के तहत नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे- सौर, पवन, और हाइड्रोजन ऊर्जा पर निवेश कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की मुहिम जारी है। वहीं, सरकारी योजनाओं के तहत पीएम स्वनिधि योजना, जैसे- छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अभियान को २०२० में शुरू किया था और इसे २०४७ तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य से जोड़ा गया है। इसके तहत रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, और कृषि जैसे सभी प्रमुख क्षेत्र आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और नीति स्तर पर काम करना होगा जो देश की समग्र ताकत और स्थिरता को बढ़ाएगा। जहां तक विदेशी निर्भरता कम करने के मुख्य उपाय की बात है तो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हैं। इसके तहत रक्षा उपकरणों, हथियारों और तकनीकी संसाधनों का अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादन करने की पहल तेज है।

भारत ने रक्षा क्षेत्र में ५वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिसमें ३,००० से अधिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। इससे विश्वों से रक्षा उपकरणों की निर्भरता कम होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। वहीं, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू उद्योगों और एमएसएमइज (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को समर्थन देने को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अयात की जगह घरेलू उत्पादन बढ़े। वहीं, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मदेनजर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संघटन (डीआरडीओ), निजी कंपनियों, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के बीच सहयोग बढ़ाकर तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने की मुहिम तेज की गई है। वहीं, औद्योगिक परीक्षितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना, निवेश और प्रोत्साहन से स्वदेशी उत्पादन को तेजी देने की पहल परवान चढ़ाई जा चुकी है। वहीं, निर्यात और व्यापार सुधार के तहत बंदरगाहों और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल

और सक्षम बनाने की मुहिम तेज है, ताकि विदेशी निर्भरता कम होकर स्वदेशी व्यापार बढ़े। वहीं, विदेशी निर्भरता घटाने के लिए ऊर्जा, कृषि, और डिजिटल क्षेत्र में स्थानीय समाधानों को अपनाने और विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए उन सरकारी नीतियों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है जो विदेशी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि चिपस (सेमीकंडक्टर चिपस) व जहाज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में ही विकसित करने होंगे ताकि विदेशी निर्भरता समाप्त हो। आत्मनिर्भरता ही देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नींव है। इस प्रकार, स्वदेशीकरण, स्थानीय उत्पादन, अनुसंधान विकास, और नीति स्तर पर सुधार करने भारत अपनी विदेशी निर्भरता कम कर सकता है। यही वजह है कि भारत में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के कई प्रभावी उपाय हैं जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं।



क्यों नहीं थम रही रुपये में गिरावट ? 48 पैसे टूटकर 88.76 प्रति डॉलर के सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली , विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि से भारत के आईटी क्षेत्र से धन प्रेषण और संभावित इक्विटी बिकवाली से जुड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। यह भारतीय मुद्रा के लिए दोहरी मार है, ऐसे समय में जब इस वर्ष विदेशी निवेश पहले से ही कमजोर है। आइए रुपये में कमजोरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि से बाजार में उथल-पुथल मचने के बीच मंगलवार को रुपये में गिरावट जारी रही। दोपहर के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 48 पैसे की गिरावट आई और यह अब तक के सबसे निचले स्तर 88.76 पर आ गया। क्यों नहीं थम रहा रुपये में गिरावट का दौर ? विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि से भारत के आईटी क्षेत्र से धन प्रेषण और संभावित इक्विटी बिकवाली से जुड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। यह भारतीय मुद्रा के लिए दोहरी मार है



ईडी के सामने तलब हुई ह्यगंदी बात फेम एक्ट्रेस अन्वेषी जैन, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में जुड़ा नाम

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तार अब लगातार फैलते जा रहे हैं। अब इस मामले में अभिनेत्री अन्वेषी जैन का नाम भी सामने आया है। इन दिनों अवैध सट्टेबाजी ऐप को लेकर ईडी सख्त है और लगातार इसमें शामिल लोगों को तलब कर रही है। इसमें अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और अभिनेता सोनू सूद से लेकर क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा तक के नाम सामने आ चुके हैं। अब इसी क्रम में अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन भी ईडी के मुख्यालय पहुंची हैं। सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक की जांच में शामिल होने के लिए अन्वेषी ईडी के ऑफिस पहुंची हैं। उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस ऐप से जुड़ा है मामला अन्वेषी को 1७ई३ सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में ईडी ने बुलाया है। कई लोगों और इन्वेस्टर के करोड़ों रुपये की ठगी करने और टैक्स चोरी करने के आरोपों के चलते ऐसे कई अवैध ऐप्स पर ईडी की व्यापक कार्रवाई हो रही है। साल 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1७ई३ समेत 174 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन लगाया था। अन्वेषी जैन की बात करें तो वो पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सिंगर और एक्ट्रेस हैं। अन्वेषी को फेम साल 2019 में एकता कपूर की सीरीज ह्यगंदी बातह्म से मिला। वह मध्य प्रदेश के जैन परिवार से आती हैं। उन्होंने एमबीए की पढ़ाई छोड़कर मुंबई का रास्ता अपनाया था। वह गंदी बात के अलावा मार्टिन, ड्रैगन, गुडिया की शादी, बॉस से लेकर हू इस यॉर डैडी जैसे शोज में काम कर चुकी हैं।



तुम हम सबकी प्यारी तानाशाह हो, स्वरा ने बेटी राबिया के जन्मदिन पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें

बेटी राबिया के जन्मदिन पर स्वरा भास्कर ने कई अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही बेटी के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की बेटी राबिया रमा अहमद आज दो साल की हो गई हैं। इस मौके पर अभिनेत्री ने बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक प्यारा नोट लिखा है। साथ ही उन्होंने बेटी के जन्मदिन के जश्न की अनदेखी तस्वीरें भी साझा की हैं। यह तुम्हारे बोलने और चलने का साल रहा स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर राबिया के जन्मदिन की कुछ तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कई तस्वीरों में दिल वाले इमोजी से राबिया का चेहरा छिपाया। हालांकि, कुछ तस्वीरों और

वीडियो में उनके चेहरे की झलक दिखाई दे रही है। राबिया हर फ्रेम में काफी खूबसूरत लग रही हैं। स्वरा ने इस पोस्ट के साथ प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ह्यदो साल और खुशी और प्यार केवल बढ़ता है। हमारे दिलों पर राज करने वाली इस प्यारी सी तानाशाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। राबू जान यह साल तुम्हारे चलने और बात करने का साल रहा है। मम्मा और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं राबू और हमेशा करते रहेंगे। तुम छोटी, प्यारी और हम सबकी दुलारी सैतान हो। हमेशा खुश, स्वस्थ, सुरक्षित और पोषित रहो। बड़ो, खिलो और मेरे दिल को खुश करो।2023 में स्वरा ने फहाद से की थी शादी स्वरा

भास्कर ने 16 फरवरी 2023 को राजनेता फहाद अहमद से शादी की थी। दोनों ने 6 जनवरी को कोर्ट में अपनी शादी की अर्जी दी थी। इसके बाद दोनों ने साधारण तरीके से कोर्ट मैरिज की थी। जबकि 23 सितंबर 2023 को स्वरा ने बेटी राबिया को जन्म दिया था। अब आज राबिया दो साल की हो गई हैं। पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं स्वरा वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों स्वरा भास्कर पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो ह्यपति पत्नी और पंगाह्म में नजर आ रही हैं। इस शो को अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं। शो में स्वरा-फहाद के अलावा और भी सेलेब्रिटी जोड़ियां हैं।

चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना चाहती हैं सबा, बताया शादी को लेकर क्या है उनकी प्लानिंग

अभिनेत्री सबा आजाद ने अपने करियर और किरदारों के बारे में बात की। साथ ही शादी के सवाल पर भी उन्होंने दी प्रतिक्रिया। जानिए क्या कुछ बताया सबा आजाद बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने अब तक के करियर में अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उनका मानना है कि उन्हें उस तरह के किरदार पसंद हैं, जहां उन्हें पूरी तरह से ढलना पड़े। अब सबा आजाद ने अपने करियर, परिवार और किरदारों को लेकर बात की। मुझे मुश्किल किरदार निभाना पसंद है हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान सबा ने बताया कि उन्हें चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना पसंद है। वो अपने करियर में अलग तरह के किरदार निभाना चाहती हैं। सबा ने कहा कि मेरे जैसे शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति का किरदार निभाना मेरे व्यक्तित्व से बहुत अलग नहीं है। लेकिन किसी के सफर का हिस्सा बनना, उसकी दुनिया में कदम रखना, यह मुझे उत्साहित करता है। मैं इस तरह के किरदारों में पूरी तरह डूब सकती हूं। मुझे ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो अपने क्षेत्र की मालिक होती हैं, जो अपनी जगह बनाने के लिए निडर होती हैं। इस तरह की ऊर्जा में कुछ शक्तिशाली होता है और मुझे इसे पढ़ें पर उतारने में मजा आता है। शादी के लिए माता-पिता ने नहीं डाला दबाव सबा पिछले काफी वक्त से अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में हैं। अक्सर दोनों की शादी को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं।



परिणीति चोपड़ा ने की यूट्यूब व्लॉग की शुरूआत, फराह खान के कुक दिलीप को किया याद, क्या है खास

परिणीति चोपड़ा जल्द ही मां बनने वाली हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्में से ब्रेक लिया है इसलिए वह अब यूट्यूब पर व्लॉग की शुरूआत कर रही हैं। जिसका शानदार वीडियो परिणीति ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने हाल ही में अपने आने वाले बच्चे की खुशखबरी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। वहीं आज परिणीति ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने यूट्यूब व्लॉग की शुरूआत करते हुए एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। परिणीति का वीडियो परिणीति ने इंस्टाग्राम पर अपना एक खास वीडियो शेयर किया। दरअसल, यह वीडियो परिणीति के पहले यूट्यूब व्लॉग का है। इस वीडियो में परिणीति पहले थोड़ी कंप्यूज दिखाई दीं कि वह किस मुद्दे को लेकर व्लॉग बनाए। लेकिन आखिर में उन्होंने बताया की वह किस विषय पर अपना व्लॉग



बनाएंगी। इस शानदार वीडियो के साथ परिणीति ने अपने व्लॉग की जानकारी देते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज दोपहर 12 बजे। मेरे यूट्यूब चैनल पर।' कैसा होगा परिणीति का व्लॉग इस वीडियो में परिणीति ने हल्के-फुल्के अंदाज में खुद पर मजाक किए और बताया कि वह खाना बनाना, पॉडकास्टिंग या नए हुनर सीखना चाहती है। आगे

परिणीति ने कहा कि व्लॉगिंग करना आसान नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा कि खाना बनाने में वह फराह खान के कुक दिलीप की बराबरी नहीं कर सकती। साथ ही, उन्होंने सही कंेटेंट चुनने की अपनी परिणामियों के बारे में भी बताया। परिणीति का करियर परिणीति चोपड़ा के करियर की शुरूआत 2011 में फिल्म 'लेडीज वर्सेज रिक्की

बहल' से हुई थी। इस फिल्म के लिए परिणीति को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। हालांकि, उन्हें असली सफलता 'इश्कजादे', 'शुद्ध देसी रोमांस' और 'हंसी तो फंसी' जैसी फिल्मों से मिली। परिणीति अभिनेत्री होने के साथ ही एक बेहतरीन गायक भी हैं। उन्होंने 'मेरी प्यारी बिंदू' और 'केसरी' जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं।

सोनी राजदान ने बेटी आलिया भट्ट के साथ शेयर कीं थोबैक तस्वीरें, फैंस बोले- 'जैसी मां वैसी बेटी'

सोनी राजदान ने अपनी बेटी आलिया भट्ट के साथ कई पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। जिसमें दोनों की समानताएं साफ दिखाई दे रही हैं। सोनी और आलिया की इन तस्वीरों पर सेलेब्स और फैंस ने जमकर प्यार बरसाया है। बॉलीवुड निमार्ता-निर्देशक महेश भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी और अपनी बेटी आलिया भट्ट की कुछ खास थोबैक तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ ही सोनी ने अपनी और आलिया की इन शानदार तस्वीरों को लेकर एक खास नोट भी लिखा। सोनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहले और अभी की कई तस्वीरें शेयर कीं। जिसमें एक तस्वीर में वह और आलिया एक जैसे पोज में नजर आ रही हैं। इन शानदार और खूबसूरत तस्वीरों के साथ सोनी ने कैप्शन में लिखा, 'पुरानी यादों से मुलाकात' सेलेब्स और फैंस के कमेंट्स शिबानी



राव हैदरी ने सोनी की तस्वीरों पर लाल दिल वाला इमोजी बनाए। एक्ट्रेस नफीसा अली सोढ़ी ने

लिखा, 'वाह मेरे सुन्दर मित्र...', ऋतिक रोशन की कथित गर्लफ्रेंड

कई समानताएं बताई हैं। एक फैन ने लिखा, 'आलिया की जुड़वा', एक

एक तस्वीर बेहद खूबसूरत है', एक और फैन ने लिखा, 'जैसी मां

की मां हैं। सोनी और आलिया मिलकर 'डिफिकल्ट डॉट्स' नाम की फिल्म बना रही हैं, जो मंजू कपूर के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म ब्रुसान के एशियन प्रोजेक्ट मार्केट में पेश की जा रही है। कहानी 1940 के दशक के लाहौर में एक पंजाबी परिवार की बेटी वीरमती की है, जो शिक्षा और प्यार के लिए सामाजिक नियमों को तोड़ती है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आलिया भट्ट का वर्कफ्रंट आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। इस फिल्म में आलिया के साथ विक्की कौशल और रणवीर कपूर नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लगातार जारी है। फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली करेंगे। इन तीनों स्टार्स को एक साथ फिल्म में देखने के लिए फैंस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घर कस्टम की रेड, जानें क्या है पूरा मामला

रकेरल में कस्टम विभाग कई जगहों पर जांच कर रही है। इसमें अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घर पर भी विभाग पहुंचा है। कस्टम विभाग केरल में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के कोच्चि स्थित आवास भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, ये रेड भूटान से लाए गए वाहनों से संबंधित है। केरल का मोटर वाहन विभाग भी यहां पहुंच गया है। भूटान से वाहन खरीदने वालों का पता लगा रहा कस्टम अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कस्टम विभाग के अधिकारी केरल में कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। इनका उद्देश्य कर चोरी के लिए फर्जी पंजीकरण के जरिए भूटान से भारत में वाहन लाने वालों का पता



लगाना है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जिनका कोडनेम ऑपरेशन नुमखोर है, उनमें मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घर भी शामिल हैं। भूटानी भाषा में 'नुमखोर' का अर्थ 'वाहन' होता है। कई जगहों पर हो रही छापेमारी कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड और मलप्पुरम सहित विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है।

कटरीना ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, पति विक्की के साथ साझा की तस्वीर; लिखा- नए चैप्टर की शुरूआत

बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ ने आश्चर्यकर तमाम अटकलों के बाद अपनी प्रेग्नेंसी का ऑफिशियल एलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने बेबी बॉप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर भी शेयर की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने मंगलवार को प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। एक्ट्रेस ने पति विक्की कौशल के साथ अपने प्रेग्नेंसी फोटोशूट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- 'हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत चैप्टर की शुरूआत करने जा रहे हैं। हमारा दिल खुशी और



कृतज्ञता से भरा हुआ है।' जान्हवी समेत कई सेलेब्स ने दी बधाई कटरीना और विक्की कौशल द्वारा इस खुशखबरी के आधिकारिक एलान के बाद तमाम सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस कड़ी में भूमि पेडनेकर ने लाल दिल वाला इमोजी बनाया है। वहीं जान्हवी कपूर ने कमेंट सेक्शन में बधाई, बधाई, बधाई लिखते हुए लाल दिल मेशन किया है। हुमा कुरैशी ने कहा, ह्यवाह शुभकामनाएं।इसके अलावा भी कई सेलेब्स बधाइयां दे रहे हैं। इतना ही नहीं उनके प्रशंसक भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। 2018 के चेक बाउंस मामले में बरी हुए राम गोपाल वर्मा, मुंबई की एक अदालत ने सुनाया फैसला कई महीनों से प्रेग्नेंसी की उड़ रही थीं अफवाहों कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर 4- महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं।

मराठवाड़ा में भारी बारिश

गोदावरी नदी के किनारे बाढ़ जैसी स्थिति; शरद पवार की अपील- मदद करे सरकार

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। धाराशिव समेत कुल 129 राजस्व इलाकों में पिछले 24 घंटों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। राकांपा (शरद पवार गुट) के प्रमुख ने सरकार से किसानों को तत्काल मदद देने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड़ जिलों में मंगलवार को भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़ने के कारण गोदावरी नदी के किनारे बाढ़ जैसी स्थिति बन

गई। धाराशिव जिला पहले से ही बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है और मराठवाड़ा के 129 राजस्व इलाकों में पिछले चौबीस घंटों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार को उन किसानों की जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए, जिन्हें भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। सोमवार की रात से मराठवाड़ा क्षेत्र के छत्रपति संभाजीनगर के जयकवाडी बांध और बीड़ के माजलगांव बांध के जलस्तर वाले इलाकों में तेज बारिश हो रही है। एक राजस्व अधिकारी ने कहा, कुछ इलाकों में ऐसा लगा जैसे बादल फट गए हों। उन्होंने बताया कि



बांधों बांध लगभग पूरी तरह भरे हुए थे और लगातार बारिश की वजह से वहां से पानी छोड़ा जा रहा था। राजस्व अधिकारी ने कहा कि माजलगांव बांध के जलस्तर वाले इलाकों

भी बताया कि जालना जिले के घनसावंगी और अम्बड तालुका व बीड़ जिले के गेवराई तालुका में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया और छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड़ जिलों के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राजस्व अधिकारी ने बताया कि रविवार को अधिक बारिश की वजह से धाराशिव के कुछ इलाके भी जलमग्न हो गए थे। सोमवार को भी परांदा, भूमें और वाशी तालुकों में तेज बारिश जारी रही। चार दिन में आठ लोगों की मौत, सरकार ने

विपक्ष के नेतृत्व वाली नगरपालिकाओं पर अर्दोंआन सरकार का वार, भ्रष्टाचार के आरोप में 13 लोग हिरासत में

अंकरा (एजेंसी)। तुर्किये की राजधानी अंकरा में नगरपालिका की तरफ से आयोजित 'कॉन्सर्ट' कार्यक्रमों में कथित भ्रष्टाचार की जांच के तहत मंगलवार को 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में पूर्व नगरपालिका कर्मी और निजी इवेंट कंपनियों के मालिक शामिल हैं। उन पर सार्वजनिक पद का दुरुपयोग और सार्वजनिक टेंडर में हेरफेर करने का आरोप है। अंकरा के मुख्य अभियोजक के दफ्तर के बयान के मुताबिक, सदियों के हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच जारी है। क्या है मामला? इस पूरी जांच का केन्द्र 2021 से 2024 तक आयोजित 32 कॉन्सर्ट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कार्यक्रमों के आयोजन की वजह से 15.4 करोड़ लीरा (लगभग 37 लाख अमेरिकी डॉलर) का वित्तीय नुकसान हुआ। यह जानकारी तुर्की के गृह मंत्रालय, वित्तीय अपराध जांच बोर्ड और कोर्ट ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट्स में दी गई है। बयान में कहा गया है कि यह मामला विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) द्वारा संचालित नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार की जांचों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। विपक्ष और सरकार के बीच शुरू हुआ विवाद विपक्षी सीएचपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोंआन की सरकार द्वारा न्यायिक माध्यम से विपक्ष को कमजोर करना है। सीएचपी ने इस मुद्दे पर कहा, सरकार का उद्देश्य विपक्ष को बदनाम करना है।



'दो-राज्य समाधान ही एकमात्र रास्ता'

इस्त्राइल-फलस्तीन विवाद पर बोला संयुक्त राष्ट्र

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बोलेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इस्त्राइल और फलस्तीन के बीच दशकों पुराने संघर्ष को सुलझाने का केवल एक ही तरीका है- दो-राज्य समाधान। उन्होंने कहा, 'हम मानते हैं कि मौजूदा चुनौतियों का हल तभी निकल सकता है जब इस्त्राइल और फलस्तीन, दो स्वतंत्र देशों के रूप में, साथ-साथ शांति और सुरक्षा के साथ रहें।' कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के बाद फ्रांस का एलान इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने फलस्तीन को औपचारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इससे



फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का यह कदम खास मान्य रखता है क्योंकि ये दोनों जी-7 समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। एमैनुएल मैक्रों ने कहा, 'यह फैसला हमारा की हार है।

दो-राज्य समाधान ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस्त्राइल और फलस्तीन शांति से रह सकेगे।' इस्त्राइल की कड़ी प्रतिक्रिया इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन घोषणाओं को 'आतंकवाद को इनाम' करार दिया। उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर के हमले के बाद फलस्तीन को मान्यता देना आतंकियों को पुरस्कृत करने जैसा है। यह कभी नहीं होगा।' नेतन्याहू ने साफ कहा कि 'जॉर्डन नदी के पश्चिम में कभी फलस्तीनी राज्य नहीं बनेगा।' इस्त्राइली विदेश मंत्रालय ने भी इन देशों के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि

शांति तभी संभव है जब फलस्तीनी प्राधिकरण आतंकवाद और भड़काऊ गतिविधियों को पूरी तरह रोके। मंत्रालय का कहना है कि 'राजनीतिक दिखावे' की बजाय देशों को हमला पर दबाव डालना चाहिए कि वह बंधकों को छोड़े और अपने हथियार डाले। इस्त्राइल-फलस्तीन विवाद पर भारत का रुख हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-राज्य समाधान के पक्ष में एक प्रस्ताव लाया गया था। भारत समेत 142 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। फलस्तीन के विदेश मंत्रालय ने कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम' बताया। 'भारत यूएन में एक

महत्वपूर्ण आवाज है' न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। इस दौरान दुजारिक ने कहा कि इस बार का बड़ा मुद्दा 'संयुक्त राष्ट्र में सुधार' है, ताकि यह संगठन 2025 की दुनिया के हिसाब से ज्यादा तेज, प्रभावी और प्रतिनिधित्वकारी बने। उन्होंने कहा, 'भारत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बहुत अहम हिस्सा है। भारत बहुपक्षवाद का मजबूत समर्थक है और महासचिव के भारत सरकार से बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे साथ कई भारतीय सहयोगी भी काम कर रहे हैं। भारत यूएन में एक महत्वपूर्ण आवाज है।'

जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज, नकदी मामले में समिति की मदद करेंगे दो वकील

नई दिल्ली (एजेंसी)। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर नोटों की जली हुई गड़ियां पाई गई थीं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। अब समिति की मदद के लिए दो वकीलों की नियुक्ति की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज हो गई है। नकदी मामले की जांच कर रही समिति की मदद के लिए दो वकीलों को नामित किया गया है। समिति की सहायता के लिए रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया गया है। पिछले महीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए राजनीतिक



आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य की एक समिति गठित की थी। अब समिति की मदद के लिए दो वकीलों की नियुक्ति की गई है। दोनों को नोटिस स्वीकार किया था। 14 मार्च को वर्मा के सरकारी आवास पर नोटों की जली हुई गड़ियां पाई गई थीं। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ

दोनों नियुक्तियां समिति के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जारी रहेंगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश की गई थी इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अगस्त, 2025 को कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश करने वाली आंतरिक जांच प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है। जस्टिस वर्मा के आवासीय

श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे भारतीय नौसेना प्रमुख, रक्षा सहयोग-समुद्री सुरक्षा पर होगी चर्चा

कोलंबो (एजेंसी)। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपने चार दिन के श्रीलंका दौरे कोलंबो पहुंचे। जहां वे प्रधानमंत्री डॉ हरिनी अमरसुर्या और सेना के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर समुद्री सुरक्षा, क्षमता वृद्धि व प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वे गॉल डायलॉग 2025 में भी हिस्सा लेंगे, जहां हिंद महासागर के बदलते परिदृश्य पर विचार होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी चार दिवसीय दौरे पर श्रीलंका रवाना हो गए हैं। इस दौरे में एडमिरल त्रिपाठी श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ हरिनी अमरसुर्या से मुलाकात करेंगे। साथ ही रक्षा सहयोग पर श्रीलंका के तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उनकी द्विपक्षीय चर्चा भी होगी, जिनमें समुद्री सुरक्षा, क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण और सहयोग की मजबूती पर जोर दिया जाएगा। नौसेना प्रमुख कोलंबो में गॉल डायलॉग 2025 के 12वें संस्करण में भी भाग लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सम्मेलन का विषय मैरिटाइम आउटलुक ऑफ द इंडियन ओशन अंडर चेंजिंग डायनेमिक्स रखा गया है। भारतीय नौसेना श्रीलंका की नौसेना के साथ नियमित रूप से वार्षिक रक्षा वार्ता, स्टफ वार्ता और अन्य ऑपरेशनल चर्चा करती है। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच साझा नौसैनिक अभ्यास (रिलेक्स), जलमार्ग अभ्यास, प्रशिक्षण और हाइड्रोग्राफी संबंधी सहयोग भी हैं। इसके अलावा दोनों नौसेनाएं इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, गॉल डायलॉग, मिलान, गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्वेरिटी कॉन्क्लेव जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भी भाग लेती हैं। भारतीय नौसेना का स्टडीलव फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा भी रविवार को कोलंबो पहुंचा है। इस दौरान सतपुड़ा के चालक दल अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ साझा नौसैनिक अभ्यास करेगा।

ट्रंप के एजेंसियों पर नियंत्रण का विवाद, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 90 साल पुराने फैसले की करेगा समीक्षा

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को फेडरल ट्रेड कमीशन की सदस्य खेचर स्लॉटर को हटाने की अनुमति दी। एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 1935 के ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा की ओर संकेत करता है, जिससे राष्ट्रपति को स्वतंत्र एजेंसियों पर और अधिक नियंत्रण मिल सकता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्वतंत्र संघीय एजेंसियों पर ज्यादा नियंत्रण देने का रास्ता खोल दिया। इसके तहत कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीएस) की उमेक्रेटिक सदस्य खेचर स्लॉटर को पद से हटाने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह



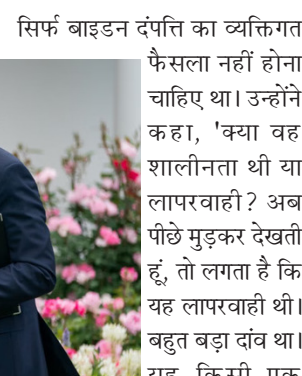
अब विचार कर रही है कि 1935 में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले को पलटा जाए या नहीं। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि स्वतंत्र एजेंसियों के कमिश्नरों से सुझाव या

लापरवाही की स्थिति में ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इससे इन एजेंसियों को कार्यपालिका से अलग एक स्वायत्त पहचान मिली थी। अब ऐसे में ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति को अपने एजेंड के लागू करने के लिए इन एजेंसियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, यागो वे इन बोर्ड सदस्यों को किसी भी कारण से हटा सके। क्यों है यह फैसला अहम? ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट 1935 के फैसले को पलटती है, तो अमेरिका की कई स्वतंत्र संस्थाएं जैसे श्रम, उपभोक्ता संरक्षण और संघीय कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी एजेंसियां राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में आ जाएंगी। इससे कार्यपालिका की शक्ति काफी बढ़ जाएगी और इन एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बड़ा असर पड़ेगा।

विवाद? विवाद तब शुरू हुआ जब टेक्सास के रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जुड़े हैं और सीनेट चुनाव लड़ रहे हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस प्रतीमा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। डंकन ने पोस्ट में लिखा, 'हम एक क्रिश्चियन (ईसाई) राष्ट्र हैं। हम टेक्सास में झुटे हिंदू भगवान की झूठी प्रतीमा को क्यों अनुमति दे रहे हैं?' इसके साथ ही उन्होंने प्रतीमा का वीडियो भी



यही कहता था कि चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला सिर्फ 'जो और जिल बाइडन का निजी निर्णय' है। लेकिन अब उन्हें लगता है कि यह



सिर्फ बाइडन दंपति का व्यक्तिगत फैसला नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'क्या वह शालीनता थी या लापरवाही? अब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो लगता है कि यह लापरवाही थी। बहुत बड़ा दांव था। यह कि सी एक

व्यक्ति के अहंकार या महत्वाकांक्षा का विषय नहीं होना चाहिए था। यह एक बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी का मामला था।' कमला हैरिस ने खुद पर

डाली जिम्मेदारी इस दौरान कमला हैरिस ने साफ कहा कि जब वे लापरवाही शब्द का इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इशारा खुद की तरफ होता है। उन्होंने माना कि उस समय उन्हें राष्ट्रपति को बाइडन से खुलकर राहना चाहिए था कि वे दोबारा चुनाव न लड़ें। लेकिन ऐसा न कर पाने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे डर था कि अगर मैं यह कहूंगी, तो लोग समझेंगे कि मैं खुद राष्ट्रपति पद के लिए मैदान तैयार कर रही हूँ। यह पूरी तरह स्वाधीन कदम माना जाता।' हैरिस ने यह दिलाया कि 2020 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की

डेमोक्रेटिक नामांकन की दौड़ में बाइडन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। बाइडन के हटने के बाद भी मुश्किलें 2024 के चुनाव में शुरूआती महीनों में बाइडन ने चुनाव लड़ने का एलान किया था। लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर से दबाव बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने जुलाई 2024 में चुनावी दौड़ से हटने का फैसला किया। इसके बाद हैरिस को पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत हासिल की।

हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर रिपब्लिकन नेता के बयान पर बवाल

'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' को लेकर की थी ये टिप्पणी

टेक्सास (एजेंसी)। अमेरिका के टेक्सास राज्य में मौजूद 90 फुट ऊंची भागवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह प्रतिमा, जिसे 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' कहा जाता है, 2024 में अनावरण की गई थी और यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे श्री चिन्मजीवर स्वामीजी की परिकल्पना में बनाया गया था और यह टेक्सास के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में मौजूद है। कैसे शुरू हुआ

विवाद? विवाद तब शुरू हुआ जब टेक्सास के रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जुड़े हैं और सीनेट चुनाव लड़ रहे हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस प्रतीमा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। डंकन ने पोस्ट में लिखा, 'हम एक क्रिश्चियन (ईसाई) राष्ट्र हैं। हम टेक्सास में झुटे हिंदू भगवान की झूठी प्रतीमा को क्यों अनुमति दे रहे हैं?' इसके साथ ही उन्होंने प्रतीमा का वीडियो भी



उनके बयान को हिंदू विरोधी और भड़काऊ करार दिया। संगठन ने